भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1503
उत्तर देने की तारीख 28 जुलाई, 2021

बीएसएनएल और एमटीएनएल हेतु पुनरुद्धार पैकेज

1503. श्री जी.एम.सिद्देश्वर

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रुग्ण एमटीएनएल और बीएसएनएल के पुनरुद्धार पैकेज को अंतिम रुप दे दिया है और इसकी घोषणा कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रस्तावित पुनरुद्धार योजना का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या उक्त दो सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के पुनरुद्धार पैकेज को अंतिम रुप देने से पहले विश्वास में लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) एवं (ख) सरकार ने दिनांक 23.10.2019 को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के लिए पुनरुद्धार योजना अनुमोदित की थी। पुनरुद्धार योजना में अन्य बातों के साथ-साथ 50 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) के जरिए स्टाफ लागत को कम करना, बजटीय आवंटन के माध्यम से वित्तपोषण की सहायता से 4जी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन, ऋण चुकाने, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन सृजित करने के लिए नॉन-कोर एवं कोर परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण, संप्रभु

गारंटी बॉण्ड जुटाकर ऋण का पुनर्गठन और बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के विलय के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन शामिल हैं।

पुनरुद्धार योजना कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. बीएसएनएल और एमटीएनएल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई है। कुल 92,956 कर्मचारियों (बीएसएनएल के 78,569 एवं एमटीएनएल के 14,387) ने वीआरएस का चयन किया। इसके परिणामस्वरुप बीएसएनएल और एमटीएनएल के वेतन व्यय में क्रमशः लगभग 50% एवं 75% की कमी आई है। सरकार ने वीआरएस पर अनुग्रह राशि की लागत को पूरा करने के लिए 16,206 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
2. वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम हेतु 24,084 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। बीएसएनएल ने अपनी आगामी 4जी निविदा में भाग लेने की इच्छुक भारतीय कंपनियों से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) के लिए दिनांक 01.01.2021 को रुचि की अभिव्यक्ति जारी की। दिनांक 01.07.2021 को 5 पात्र बोलीदाताओं को आशय-पत्र जारी किए गए हैं।
3. सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को क्रमशः 8,500 करोड़ रुपए और 6,500 करोड़ रुपए की सप्रंभु गारंटी प्रदान की हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों ने बॉन्ड जुटाए हैं और उच्च लागत वाले वर्तमान ऋण को चुकाने के लिए निधियों का उपयोग किया है।
4. मुद्रीकरण के जरिए बीएसएनएल/एमटीएनएल की परिसंपत्तियां चिन्हित की गई हैं। चरण-I में डीआईपीएएम रुट के माध्यम से बीएसएनएल की 4 संपत्तियों और एमटीएनएल की 2 संपत्तियों को बोली के लिए संसाधित कर दिया गया है।
5. बीएसएनएल को सरकारी सहायता के रुप में, इंटरनेट/ब्रॉडबैंड, लैडंलाइन और लीज्ड लाइन आवश्यकताओं के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/स्वायत निकायों आदि द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल की क्षमताओं के अनिवार्य उपयोग के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

(ग) एवं (ख) इस पुनरुद्धार योजना को बीएसएनएल के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद और एमटीएनएल के लिए परामर्शदाता की सिफारिशों पर विचार करते हुए तैयार किया गया है। इन संस्थानों द्वारा अपनी सिफारिशें तैयार करने के क्रम में कर्मचारी संघों/अधिकारी संघों/कर्मचारियों से परामर्श लिया गया है। बीएसएनएल और एमटीएनएल बोर्ड द्वारा इन पुनरुद्धार योजनाओं की सिफारिश की गई थी।

******